30 तक तैयार हो जाएगा अंतिम पैनल

अगले माह 10 हजार से अधिक को नियुक्ति पत्र

दैनिक जागरण 20-12-13

- 26 जनवरी तक लग जाएंगे काम पर
- स्नातक नहीं, सब इंजीनियर मिले

जागरण ब्यूरो, पटना : राज्य सरकार अगले माह 10677 लोगों को नियुक्ति पत्र देने जा रही है। ये इंदिरा आवास की निगरानी आदि का काम करेंगे। इंदिरा आवास योजना के तहत जब तक केंद्र सरकार द्वारा प्रशासनिक खर्च की अनुमति दी जाएगी तब तक नियोजन बरकरार रहेगा।

6 लाख आवेदन, 4 माह में नियोजन : इसी साल सितंबर महीने में राज्य मंत्रिपरिषद ने इस योजना को मंजूरी दी। 19 अक्टूबर को आनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया। 10677 पदों के लिए करीब छह लाख लोगों ने आनलाइन आवेदन किए। स्वीकृत पदों के विरुद्ध चार गुना लोगों का पैनल अंकों के आधार पर तैयार किया गया है। इस मेरिट लिस्ट को गुरुवार को आनलाइन कर दिया गया है। कोई भी किसी भी व्यक्ति का मेरिट-अंक देख सकता है। सुझाव एवं आपत्ति के लिए 26 दिसंबर तक का समय दिया गया है। उसके निराकरण के बाद 30 दिसंबर तक अंतिम सूची जारी की जाएगी।

दिलचस्प : ग्रामीण विकास मंत्री के अनुसार ग्रामीण इलाकों में रहने वाले इतना आइटी फ्रेंडली हो गए कि छह लाख आवेदन आनलाइन आए। 5-6 हजार लोगों ने क्वेयरी किया। ई-मेल से उत्तर दिया। 11500 रुपये मासिक पर ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता स्नातक रखी गई थी। और उच्च डिग्री के लिए अधिक अंक का प्रावधान था। प्रखंड स्तर पर 921 ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक की दरकार है। दिलचस्प यह कि सारे पदों के लिए इंजीनियर (बीई) मिले हैं। इसी तरह 8422 ग्रामीण आवास सहायक के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता प्लस-टू थी मगर सारे के सारे स्नातक मिले। लेखापाल के लिए बी. काम की दरकार थी मगर सीए या एम काम मिले।